

	: : आयुक्त (अपील) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : : O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE	 सत्यमेव जयते
	द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2 nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road राजकोट / Rajkot - 360 001 Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in DIN20221264SX000000D280	

क अपील / फाइल संख्या / मूल आदेश नं / दिनांक / Date
 Appeal / File No. O.I.O. No. 3/3/2022
 V2/82/BVR/2022 BHV-EXCUS-000-ADC-VM-020-2021-22

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):
BHV-EXCUS-000-APP-130-2022

आदेश का दिनांक / जारी करने की तारीख /
 Date of Order: 26.12.2022
 Date of issue: 28.12.2022

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील), राजकोट द्वारा पारित /
 Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अथवा आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से वृत्तित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Dipakbhai Nathuram Aswani, 1, Shiv Chambers, Opp. People's Bank, Wadhwan, Dist.: Surendranagar, Gujrat- 363031

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। / Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मुद्दाओं से सम्बंधित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, अरु के पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बतौर गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली मकान असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bhaunali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में भेज दिया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करी। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी प्राबलिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेजॉल्वेड बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उक्त शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर निवन्धनी, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ वित्त आदेश के निरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करी। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी प्राबलिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेजॉल्वेड बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उक्त शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-



- (i) विद्युत अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत बर्ष की गयी अपील, सेवाकर नियमवानी, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें। (उन्हें से एक प्रति प्रमाणीकृत होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा प्रदायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की विद्युत अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि वह करीब रूप से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 की के अंतर्गत रकम
(ii) सेमिस्ट जमा की गयी राशि
(iii) सेमिस्ट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान विद्युत (सं-2) अधिनियम 2014 के अंतर्गत से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्वगन अर्थात् अपील को लागू नहीं होगी।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपूरतक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि मांग के किसी मुकदमा के मामले में, जहां मुकदमा किसी मात्र को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में मांग के प्रदर्शन के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में मांग के मुकदमा के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे मांग के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे मास पर लगी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को मांग निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो अट्टी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विद्युत अधिनियम (नं 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा निर्यात की गई शारीक अथवा समायाचिधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अयाचनी के साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अयाचनी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आवेदों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की निम्न प्राई कार्य के बनने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आवेदन एवं स्वगन आवेदन की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in की देख लें। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.



:: अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Dipakbhai Nathuram Aswani, Wadhwan, Dist.: Surendranagar
 (hereinafter referred to as "Appellant") has filed the present Appeal against
 Order-in-Original No. BHV-EXCUS-000-ADC-VM-020-2021-22 dated 03.03.2022
 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Additional
 Commissioner, Central GST, HQ, Bhavnagar (hereinafter referred to as
 'adjudicating authority').

2. The facts of the case, in brief, are that the Income Tax Department shared the third party information/ data based on Income Tax Returns/ 26AS for the Financial year 2015-16 of the Appellant. Letter dated 30.03.2019 was issued by the Jurisdictional Range Superintendent requesting the Appellant to provide information/ documents for the Financial year 2015-16. A summon dated 23.09.2020 was also issued to the Appellant to provide the details. However, no reply was received from the Appellant.

3. In absence of data/information, a show cause notice dated 29.12.2020 was issued to the Appellant, demanding Service Tax and cess to the tune of Rs. 1,37,52,166/- under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') alongwith interest under Section 75 of the Act. It was also proposed to impose penalties under Section 78, 77(2) and 77(1)(c) of the Act upon the Appellant.

4. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed Service Tax demand of Rs. 10,27,194/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act and dropped the demand of Rs. 1,27,24,972/-. The Adjudicating Authority imposed penalty of Rs. 10,27,194/- under Section 78 and penalty of Rs. 10,000/- each under Section 77(2) and 77(1)(c) of the Act.

5. Being aggrieved, the Appellant has preferred the present appeal on various grounds as stated below:

(i) The Adjudicating Authority erred in confirming the demand based on the wrong understanding that the Appellant had claimed exemption under Entry No. 12(a) of the Notification No. 25/2012-Service Tax despite the fact that they had never claimed that but they were claiming exemption under entry no. 13(a). The Adjudicating Authority has not recorded any reason why they are not entitled for exemption under Entry No. 13(a) of the said Notification.

(ii) The Adjudicating Authority erred in confirming the demand for services provided of construction/ repair/ maintenance of roads merely because of the fact that such activities are also undertaken for the attached structure like entry gate, guard cabin and protection wall despite the fact that in terms of Section 66F(3) such services are naturally bundled and shall be treated as services related to roads only which is giving essential character of the contract.



(Signature)

(iii) The Show Cause Notice was issued without any investigation and merely based on third party data despite it is well settled principle that such Show Cause Notice cannot be issued in violation of judicial discipline as per decision in the case of M/s. Amrish Rameshchandra Shah (Bombay High Court), Sharma Fabricators & Erectors Pvt. Ltd. - 2017 (5) GSTL 96 (Tri.-All.) etc. were bought to the notice of the Adjudicating Authority.

(iv) The Adjudicating Authority erred in invoking extended period of limitation despite the fact that there is not an iota of evidence which suggests suppression on their part since they were under bona fide belief that their services were exempted. The Adjudicating Authority also erred in imposing penalty under Section 78(1) of the Act and other penalties despite the fact that neither there is suppression on their part nor any tax is payable.

6. The matter was posted for hearing on 13.12.2022. CA Punit Prajapati appeared for personal hearing in a virtual mode and reiterated the submissions made in the appeal. He submitted that the Appellant was providing road construction service to Government Department which are exempt and the Adjudicating Authority had dropped demands in all 90 cases, except this one. He submitted that in the present case forest department has awarded contract for construction of road alongwith boundary wall. However, Adjudicating Authority has denied exemption considering it as construction of wall only. Actually wall is integral part of the road. Even if it is treated as composite contract, the same has to be classified as road construction service according to the main activity. Even if the same is not accepted, Adjudicating Authority should have charged tax on proportionate basis after allowing the applicable rebate. Therefore, he requested to set aside the Order-In-Original and allow the appeal.

7. I have carefully gone through the case records, impugned order and appeal memorandum filed by the Appellant. I find that the issue to be decided in the case on hand is whether the activity carried out by the appellant is liable to Service Tax or otherwise.

8. I find that Show Cause Notice had been issued without verifying any data or nature of services provided by the Appellant as the same had been issued only on the basis of data received from the Income Tax department.

9. I find that out of total demand of Rs. 1,37,52,166/-, the Adjudicating Authority vide the impugned order, dropped the demand of Rs. 1,27,24,972/- and confirmed the demand of 10,27,194/-. The confirmed demand is in three parts. First is the income of Rs. 26,940/- received from Shri Ajaykumar Hiralal Thakur as shown in Form 26AS on which TDS under Section 194H was deducted and the Appellant had not submitted any reply/ documents for claiming exemption from Service Tax and hence the Adjudicating Authority confirmed the demand of Rs. 3,906/-. I find that the Appellant has not contested this demand



in their grounds of appeal nor submitted any documents for claiming exemption thereon. Therefore, I am of considered view that the Appellant is liable to Service Tax.

9.2 The second part of the confirmed demand is on income of Rs. 40,792/- earned from Project Implementation Unit. I find that the Appellant has not submitted any documents before Adjudicating Authority for claiming exemption from Service Tax. On going through the appeal memorandum, the Appellant has not submitted any grounds/ supporting documents for claiming exemption on this also. Therefore, I find that the Appellant is liable to Service Tax of Rs. 5,915/- as demanded in the impugned order.

9.3 The third part of the confirmed demand is on income of Rs. 70,16,364/- earned by the Appellant from Deputy Conservator of Forests and the Appellant has not submitted any work order/ contract/ agreement issued by the RFO, Surendranagar before the Adjudicating Authority. However, the Appellant submitted 9 invoices in this regard before the Adjudicating Authority as per which the work carried out by the Appellant is construction of approach C.C. Road, security Guard cabin, entry gate and Protection Wall at Surendranagar, Thangadh, Chotila, Dhrangadhra and Kharaghoda Range Forest Office. The Adjudicating Authority found that such construction of Guard Room Protection Wall falls under "construction related to a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession" and the said service provided to the Government, a local authority or a governmental authority was exempted upto 31.03.2014 under Clause 12(a) of the Notification No. 25/2012-Service Tax dated 30.06.2012 and the said exemption was withdrawn by virtue of Notification No. 6/2015-Service Tax dated 01.03.2015 w.e.f. 01.04.2015 by omitting the entry No. 12(a) of the Notification No. 25/2012-Service Tax.

9.4 I find that the Appellant produced copy of tender acceptance letter dated 04.12.2015 issued by the Deputy Conservator of Forest, Surendranagar wherein the subject is mentioned as "construction of approach C.C. road, security guard cabin, entry gate and protection wall work". It is the findings of the Adjudicating Authority that this work falls under Entry No. 12 (a) of the Notification No. 25/2012-Service Tax whereas, the contention of the Appellant is that this work falls under Entry No. 13(a) of the said Notification. The sub-clause (a) of Entry No. 12 was omitted vide Notification No. 6/2015-Service Tax dated 01.03.2015 w.e.f. 01.04.2015. To verify the claim of the Appellant the entry No. 13 is re-produced below:

13. Services provided by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,-
(a) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use by general



[Handwritten signature]

public;

9.5 I also find that the work assigned to the Appellant is a composite work order for construction of approach C.C. road, security guard cabin, entry gate and protection wall for various Range Forest offices falling under Surendranagar Range Forest. This works carried out by the Appellant is meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession which is to be used by the Government authority and/or general public only. Therefore, there is force in argument advanced by the Appellant and accordingly, the Appellant is not liable to pay Service Tax on the income earned from RFO, Surendranagar.

10. In view of the above discussions and findings, I set aside the impugned order confirming the demand of Service Tax of Rs. 10,17,373/- and I uphold the impugned order confirming the demand of Rs. 3,906/- and Rs. 5,915/- as discussed in para *supra*, alongwith Interest and penalties under Section 78, 77(2) and 77(1)(c) of the Act. However, due to re-calculation of Service Tax amount, I extend benefit of reduced penalty as envisaged under proviso to Section 78 of the Act subject to fulfilment of the conditions of the said proviso.

11. In view of discussions and finding, I partially set aside the impugned order and partially allow the appeal filed by the Appellant.

12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

12. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested



Superintendent
Central GST (Appeals)
Rajkot


(शिव प्रताप सिंह)/(Shiv Pratap Singh),

आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s. Dipakbhai Nathuram Aswani, 1, Shiv Chambers, Opp.: People's Bank, Wadhwan, Dist.: Surendranagar-363031.	सेवा में, मे० दीपकभाई नथुराम असवाणी, 1, शिव चेंबर्स, पीपल्स बैंक के सामने, वडवाण, जिला: सुरेन्द्रनगर-363031।
--	---

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अपर/संयुक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सुरेन्द्रनगर मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5) गार्ड फाइल।

